

रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

शिवम अग्रवाल^{1*} | मनीष कुमार शुक्ला²

¹शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

²प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

*Corresponding Author: shivamag1993@gmail.com

सार

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) रीवा संभाग में युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का शासन स्तर पर एक प्रभावशाली प्रयास रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार या स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है। योजना से महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। हालांकि, प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता, कोर्स की प्रासंगिकता और प्लेसमेंट की सीमाएं योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। यदि योजना के कार्यान्वयन में सुधार किया जाए, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और रोजगार से बेरोजगार युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाय, तो यह योजना रीवा संभाग में युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन सकता है।

शब्दकोश: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन।

प्रस्तावना

भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या में एक बड़ी भागीदारी युवाओं की है। इस जनसांख्यिकीय लाभ को उत्पादकता में बदलने के लिए आवश्यक है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक कौशल प्रदान किया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य देश के उन युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना जो शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं या जिनके पास रोजगार लायक कोई औपचारिक कौशल नहीं है। यह योजना देश में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास के रूप में देखी जा रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) के अधीन संचालित की जा रही है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से हो रहा है। इस योजना के तहत देशभर में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जैसे— रिटेल, कस्टमर सर्विस, आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रिकल, हेल्थकेयर, प्लम्बिंग, ऑटोमोबाइल, मोबाइल रिपेयरिंग आदि। इस योजना में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रमाणपत्र तथा कुछ मामलों में स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिससे वे स्वरोजगार अथवा रोजगार प्राप्त कर सकें।

भारत के मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह संभाग प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े और आंशिक रूप से

संसाधनों के उपलब्धता से वंचित क्षेत्रों में शामिल है। रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर जैसे जिले आते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण हैं परंतु बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की कमी और सीमित औद्योगिक अवसर जैसी समस्याओं से ग्रसित भी हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि या दैनिक मजदूरी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, सीमित संसाधन और अस्थिर आय के कारण कृषि भी स्थायी विकल्प नहीं रह गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम रीवा संभाग के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभर रहा है।

रीवा संभाग में चड्ढाटल के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कई प्रशिक्षण केंद्र शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी स्थापित किए गए हैं, ताकि योजना की पहुँच अधिकतम युवाओं तक हो सके। इस योजना में विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। यह देखा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई लाभार्थियों ने स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्रारंभ किये हैं, जबकि कुछ लोग को निजी कंपनियों में रोजगार भी मिला है। रीवा और सतना में ब्यूटी पार्लर संचालन, सिंगरौली में हेल्थकेयर और बिजली संबंधी कार्यों तथा सीधी में मोबाइल रिपेयरिंग और सिलाई-कढ़ाई जैसे ट्रेडों में युवाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है।

इस योजना की सफलता के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी सामने आयी और अनेक मामलों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। प्रशिक्षकों की योग्यता, संसाधनों की कमी, कोर्स की स्थानीय रोजगार बाजार से असंगति तथा प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट की कमी प्रमुख समस्याओं के रूप में उभरी है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी का अभाव और सामाजिक रूढ़ियों के कारण भी महिलाओं और पिछड़े वर्ग के युवाओं की सहभागिता सीमित रही। फिर भी यह योजना रीवा संभाग जैसे क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है क्योंकि इसने न केवल युवाओं को प्रशिक्षित किया बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। पहले जहाँ युवक-युवतियाँ रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते थे, वहीं अब कुछ हद तक स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के अवसर सृजित हो रहे हैं। महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है और सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन देखा गया है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने रीवा संभाग में किस प्रकार से युवाओं के जीवन पर प्रभाव डाला है, किस हद तक यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है और कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों के अनुभव, प्रशिक्षण केंद्रों की कार्यप्रणाली, स्थानीय प्रशासन की भूमिका और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह योजना युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि रीवा क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन कितनी प्रभावशीलता से हुआ है। अतएव शोध अध्ययन से संबंधित निम्न उद्देश्यों को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है—

- रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार/स्वरोजगार की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण एवं संबंधित सेवाओं से लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करना।

शोध विधि

इस अध्ययन में रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों, प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं संबंधित अधिकारियों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है। वहीं द्वितीयक आंकड़ों के लिए सरकार की रिपोर्टें, योजना संबंधी दस्तावेज और संबंधित विभागों के आंकड़ों का उपयोग किया गया। सैंपल चयन के लिए सुविधाजन्य नमूना विधि (Convenient Sampling Method) अपनाई गई, जिसमें विभिन्न ट्रेडों से प्रशिक्षित युवाओं को शामिल किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि योजनायुवाओं के जीवन, रोजगार और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला है। इस शोध में क्षेत्रीय असमानताओं, लिंग आधारित भागीदारी और योजना की चुनौतियों का विशेष ध्यान रखते हुए निष्कर्ष निकाले गये हैं। संपूर्ण शोध प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और प्रमाणिक रूप में संपन्न किया गया है।

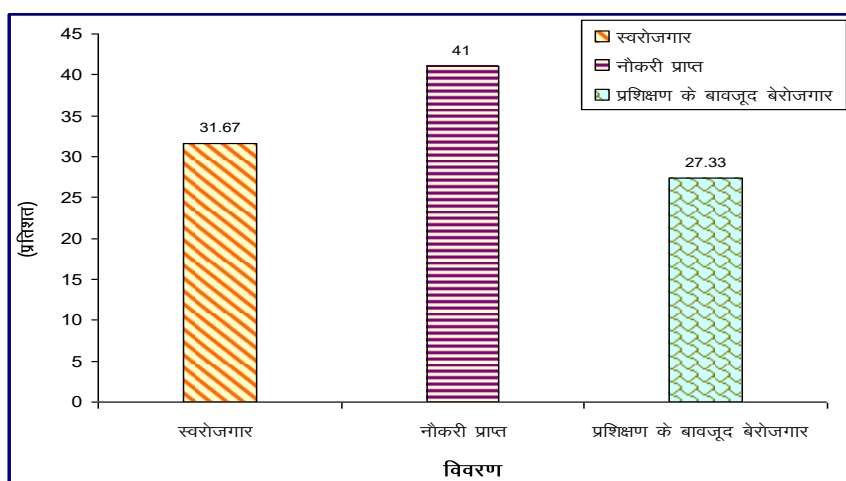
विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से संबंधित है, जिसके लिए रीवा संभाग की तहसीलों से प्राथमिक स्तर पर दैव-निर्दर्शन प्रविधि के सविचार विधि से समग्र में से चयनित किये गये कुल 300 लाभार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया गया है और इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर संग्रहित आंकड़ों को सरल व बोधगम्य बनाने हेतु उन्हें वर्गीकृत कर सारणीबद्ध किया गया है, जो इस प्रकार है—

सारणी 1: रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार की स्थिति

क्रमांक	विवरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	स्वरोजगार	95	31.67
2.	नौकरी प्राप्त	123	41.00
3.	प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार	82	27.33
कुल योग		300	100.00

स्रोत— व्यक्तिगत सर्वेक्षण।



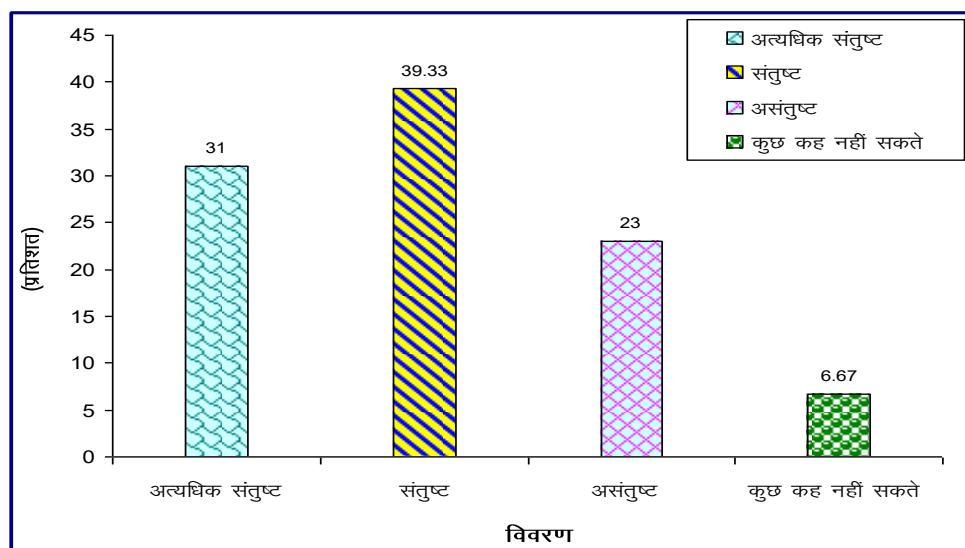
आरेख 1: रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार की स्थिति।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 एवं आरेख के अवलोक से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, जिसे सर्वेक्षित व्यक्तियों में से 95 लोगों ने बतलाया है कि इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं जिनका प्रतिशत 31.67 है, जबकि वहीं चयनित लाभार्थियों में से 123 लोगों ने बतलाया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् नौकरी के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिनका प्रतिशत 41.00 है और 82 लोगों ने बतलाया कि इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं जिनका प्रतिशत 27.33 है। अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त हो रहे हैं।

सारणी 2: अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण एवं संबंधित सेवाओं से लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर का विवरण

क्रमांक	विवरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	अत्यधिक संतुष्ट	93	31.00
2.	संतुष्ट	118	39.33
3.	असंतुष्ट	69	23.00
4.	कुछ कह नहीं सकते	20	6.67
कुल योग		300	100.00

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण।



आरेख 2: अध्ययन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण एवं संबंधित सेवाओं से लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर का विवरण।

उक्त सारणी क्रमांक 02 एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने व उससे संबंधित सेवाओं से 188 लाभार्थियों ने बतलाया कि वे अत्यधिक सन्तुष्ट हैं, जिनका प्रतिशत 39.33 है जबकि वहीं 93 लाभार्थियों ने बतलाया है कि वे अत्यधिक सन्तुष्ट हैं जिनका प्रतिशत 31.00 है। इसी प्रकार 69 लाभार्थियों ने बतलाया है कि वे इससे असन्तुष्ट हैं जिनका प्रतिशत 23.00 है तथा चयनित लाभार्थियों में से शेष 20 उत्तरदाताओं ने बतलाया है कि इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 6.67 है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण एवं संबंधित सेवाओं से लाभार्थियों का कल्याण हो रहा है और इससे उनका आर्थिक विकास भी सम्भव हो रहा है जिससे लाभार्थी वर्ग सन्तुष्ट हैं।

शोध की समस्या एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों पर किये गये अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस योजना ने युवाओं को कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसके प्रभावों में कुछ प्रमुख समस्याएं भी देखी गई हैं। सबसे पहली समस्या है प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता। कई प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षकों की योग्यता व संसाधनों की कमी देखी गई, जिससे प्रशिक्षण प्रभावी नहीं हो पाया। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि प्रशिक्षण के बाद भी लाभार्थियों को रोजगार नहीं मिल पाया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और स्वरोजगार के लिए पूंजी व मार्गदर्शन की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ लाभार्थियों को उनके प्रशिक्षण के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाया, जिससे उनके कौशल का समुचित उपयोग नहीं हो सका।

इन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसा कि प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए एवं प्रशिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाये, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा, मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाये। इसके अलावा स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों को रोजगार से जोड़ने की नीति अपनाई जाये, जिससे योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव अधिक प्रभावशाली हो सके।

निष्कर्ष

रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि इस योजना से क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेड्स में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता में वृद्धि होती है और वे स्वरोजगार करने व रोजगार के योग्य बन रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के युवाओं, महिलाओं और स्कूली शिक्षा से वंचित लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार और लघु उद्यमों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिला है। कई लाभार्थियों ने प्रशिक्षण के उपरांत स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त किये हैं या स्वयं का व्यवसाय शुरू किये हैं, इससे रीवा संभाग में बेरोजगारी की दर में आंशिक कमी आई है। निष्कर्षतः यह योजना रीवा संभाग के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक सार्थक कदम रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, रमेश कुमार — प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : एक मूल्यांकन अध्ययन. नई दिल्ली, शिक्षा प्रकाशन, 2019
2. मिश्रा, सीमा — कौशल विकास और ग्रामीण रोजगार, भोपाल : मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अकादमी, 2020
3. भारत सरकार — प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (छड़ज़टल) की वार्षिक रिपोर्ट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, 2021
4. त्रिपाठी, अजय — रीवा संभाग में युवाओं की रोजगार स्थिति और कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव, भारतीय सामाजिक शोध जर्नल, खंड 12, अंक 3, 2022

